



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 127]

नई दिल्ली, सोमवार, जून 19, 2006/ज्येष्ठ 29, 1928

No. 127]

NEW DELHI, MONDAY, JUNE 19, 2006/JYAISTA 29, 1928

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

( वाणिज्य विभाग )

( पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय )

आधिसूचना

नई दिल्ली, 15 जून, 2006

जांच शुरूआत

( निर्णायक समीक्षा )

विषय : साऊदी अरेबिया और रूस के मूल की या वहां से निर्यातित हैक्सामाइन के आयात पर लगाए गए निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क की निर्णायक समीक्षा की शुरूआत ।

सं. 8/1/2001 ( एसएसआर )-डीजीएडी.- 1995 में यथा संशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975

और सीमाशुल्क टैरिफ ( पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन एवं संग्रहण और क्षति निर्धारण ) नियम, 1995 को ध्यान में रखते हुए निर्दिष्ट प्राधिकारी ( जिसे इसके बाद प्राधिकारी कहा जाएगा ) साऊदी अरेबिया और रूस ( जिसे इसके बाद संबद्ध देश कहा जाएगा ) के मूल की या वहां से निर्यातित हैक्सामाइन ( जिसे इसके बाद संबद्ध वस्तु कहा जाएगा ) के आयात पर अनंतिम पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश करते हैं । प्राधिकारी के प्रारंभिक जांच परिणामों को दिनांक 15.5.2001 के द्वारा प्रकाशित किया गया था । दिनांक 15.2.2002 की अधिसूचना द्वारा अधिसूचित प्राधिकारी के अंतिम जांच परिणाम और दिनांक 28.6.2001 की अधिसूचना सं. 74/2001-सीमाशुल्क के द्वारा राजस्व विभाग द्वारा लगाए गए अनंतिम शुल्क के आधार पर राजस्व विभाग द्वारा दिनांक 27.3.2002 की अधिसूचना सं. 31/2002-सीमाशुल्क के द्वारा संबद्ध देश से आयातित संबद्ध वस्तु पर निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाया गया है ।

## 2. समीक्षा हेतु अनुरोध

यतः सीमाशुल्क टैरिफ (संशोधन) अधिनियम 1995 के अनुसार लगाया गया पाटनरोधी शुल्क, यदि पहले समाप्त नहीं किया जाएगा, तो यह लागू किए जाने की तारीख से पांच वर्ष की अवधि समाप्त होने पर निष्प्रभावी हो जाएगा ।

और यतः उपर्युक्त नियमों के तहत प्राधिकारी के लिए यह आवश्यक है कि पाटनरोधी शुल्क को लगातार लगाए रखने की आवश्यकता की समय-समय पर समीक्षा की जाए और यदि वह उसके द्वारा प्राप्त सूचना के आधार पर इस बात से संतुष्ट है कि ऐसे शुल्क निरंतर लगाए जाने का कोई औचित्य नहीं है, उत्तराधिकारी इसको वापस लेने के लिए केन्द्र सरकार को सिफारिश कर सकता है । उपर्युक्त प्रावधान में किसी बात के होते हुए भी प्राधिकारी के लिए उपाय की समाप्ति की तारीख से पहले उचित समय के भीतर घरेलू उद्योग द्वारा अथवा उसकी ओर से किए गए विधिवत पर्याप्त अनुरोध के आधार पर समीक्षा करना अपेक्षित है । चाहे शुल्क की समाप्ति से पाटन और क्षति अथवा पुनरावृत्ति होने की संभावना हो ।

और यतः उक्त प्रावधानों के अनुसार घरेलू उद्योग ने ऐसी समीक्षा के लिए अनुरोध करते हुए एक विधिवत सिद्ध याचिका के साथ प्राधिकारी से अनुरोध किया है, विनिर्दिष्ट प्राधिकारी यह समझते हैं कि लागू पाटनरोधी शुल्क के लिए निर्णायक समीक्षा की कार्रवाई शुरू करना उचित रहेगा ताकि पाटन को रसमाप्त करने हेतु ऐसे शुल्क को लगाए रखने की आवश्यकता की जांच की जा सके, चाहे शुल्क को हटा लिए जाने अथवा परिवर्तित किए जाने अथवा दोनों कर दिए जाने से क्षति के जारी रहने अथवा दुबारा होने की संभावना हो ।

## 3. समीक्षा के लिए आधार

यह अनुरोध लागू पाटनरोधी शुल्कों को जारी रखने और बढ़ाने के लिए है । यह अनुरोध इन आधारों पर आधारित है कि साउदी अरेबिया और रूस से संबद्ध वस्तु के आयात पर पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के बावजूद पाटन जारी रहा है और घरेलू उद्योग को संबद्ध देशों से पाटन के कारण क्षति हो रही है । आवेदक ने यह भी तर्क दिया है कि इस देश के विरुद्ध उपायों की समाप्ति से घरेलू उद्योग को क्षति और पाटन की पुनरावृत्ति अथवा जारी रहने की संभावना है ।

आवेदक ने यह भी दावा किया है कि लागू पाटनरोधी शुल्क घरेलू उद्योग को उचित राहत देने के लिए पर्याप्त नहीं है और पाटनरोधी उपायों को समाप्त करने के फलस्वरूप घरेलू उद्योग को गहन क्षति होगी। इसलिए, शुल्क को उचित वृद्धि के साथ अगले पाँच वर्ष के लिए निरंतर लगाए रहने की आवश्यकता है।

#### 4. जांच प्रारंभ

समीक्षा की आवश्यकता को सिद्ध करते हुए घरेलू उद्योग द्वारा प्रत्युत सकारात्मक साक्ष्य के आधार पर स्वयं संतुष्ट होने पर प्राधिकारी एतद्वारा लागू शुल्क को लगातार लगाए रखने की आवश्यकता की समीक्षा करने के लिए पाटनरोधी नियमावली के नियम 23 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9 क (5) के अनुसार समीक्षा प्रारंभ करते हैं कि क्या शुल्क की समाप्ति से पाटन और क्षति के जारी रहने अथवा पुनरावृत्ति होने की संभावना होगी।

#### 5. विचाराधीन उत्पाद

वर्तमान जांच में अंतर्ग्रस्त उत्पाद हैक्सा माइथाइलिन टैट्रामाइन है जिसे बाजार में हैक्सामाइन भी कहते हैं। यह एक सफेद रवेदार पाउडर है जिसका मीठा धात्तिक र्खाद है। शुद्ध रूप में यह रंगीन और गंदहीन है। यह रोम्बिक ड्रॉकॉहैड्रोन्स में रवेदार बनता है। यह अमोफोरम, मैथानिमाइन, क्रिस्टामाइन, शिष्टोजैन यूरोट्रोपाइल के रूप में भी ज्ञात है। इसे सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के सीमाशुल्क उपशीष 2921.29 के अंतर्गत वर्गीकृत है। भूल जांच में जांचा गया उत्पाद हैक्सामाइन था इसलिए वही उत्पाद इस जांच के व्याप्ति में शामिल किया जाएगा।

#### 6. प्रक्रिया

(I) जांच में यह निर्धारित किया जाएगा कि क्या उपायों की समाप्ति से पाटन और क्षति जारी रहने अथवा दुबारा होने की संभावना होगी। प्राधिकारी यह जांच करेंगे कि पाटन को समाप्त करने के लिए शुल्कों को निरंतर लगाए रखना आवश्यक है और क्या यदि शुल्क को हटा दिया जाए अथवा परिवर्तित कर दिया जाए अथवा दोनों कार्य होने पर क्षति के जारी रहने अथवा दुबारा होने की संभावना होगी।

- (ii) समीक्षा में दिनांक 15-2-2002 की अधिसूचना के सभी पहलू शामिल होंगे।
- (iii) इस समीक्षा में शामिल देश सऊदी अरब और रूस हैं।
- (iv) वर्तमान समीक्षा के प्रयोजनार्थ जांच की अवधि 1 अप्रैल, 2005 से 31 मार्च, 2006 तक है।
- (v) उपर्युक्त नियम के नियम 6,7,8,9,10,11,16,17,18,19 और 20 के प्रावधान इस जांच में कुछ संशोधनों के साथ लागू होंगे।

#### (II) सूचना का प्रस्तुतिकरण

संबद्ध देशों के निर्यातक, भारत में अपने दूतावासों के जरिए उनकी सरकारें, भारत में आयातक और प्रयोक्ता जो संबंधित हैं तथा घरेलू उद्योग को निर्धारित फार्म और तरीके से संबंधित सूचना प्रस्तुत करने के

लिए अलग से संबंधित किया जा रहा है और उनके विचार निम्नलिखित पते पर प्राधिकारी के ध्यान में लाए जाएँ :-

विनिर्दिष्ट प्राधिकारी,  
पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय  
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य टिमाग, उद्योग भवन  
नई दिल्ली-110011 : फ़ैक्स 91-11-23063418

कोई अन्य हितबद्ध पक्ष भी निम्नलिखित निर्धारित समय सीमा के भीतर निर्धारित कार्म और तरीके से जांच में संगत निवेदन कर सकता है। कोई पक्षकार जो प्राधिकारी के समक्ष गोपनीय निवेदन करे, उसके लिए अन्य पक्षकारों को उपलब्ध कराने हेतु उसका अगोपनीय रूपांतर प्रस्तुत करने की आवश्यकता है।

### (iii) समय सीमा

वर्तमान निर्णायक समीक्षा से रांबोधीत वाइ रूचना और सुनवाइ के लिए कोई अनुसाध लेनी चाहिए ताकि वह निर्णायक समीक्षा की अधिसूचना की प्रकाशन की तारीख से चालीस (40 दिन) दिनों के भीतर उपर्युक्त पते पर प्राधिकारी के पास पहुँच जाए। यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर भूमि प्राप्त नहीं होती है अथवा प्राप्त रूचना अपूर्ण है तो निर्दिष्ट प्राधिकारी अपने जांच परिणामों को उच्च नियम के अनुसार रिकार्ड में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर रिकार्ड कर सकता है।

### IV. सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण

नियम 6(7) के अनुसार कोई हितबद्ध पक्षकार अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य की अगोपनीय रूपांतर वाली सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण कर सकता है। यदि कहीं कोई हितबद्ध पक्षकार सूचना देने से इंकार करता है अथवा अन्यथा एक उचित अवधि के भीतर आवश्यक सूचना प्रदान नहीं करता है अथवा पर्याप्त रूप से जांच में बाधा डालता है तो प्राधिकारी अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर जांच परिणाम रिकार्ड कर सकता है और केन्द्र सरकार को ऐसी सिफारिशें कर सकता है जो वह उचित समझे।

**MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**  
**(Department of Commerce)**  
**(Directorate General of Anti-Dumping & Allied Duties)**

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 15th June, 2006

**Initiation**

**(Sunset Review)**

**Subject : Initiation of Sunset Review of the definitive anti-dumping duty imposed on import of Hexamine originating in or exported from S. Arabia and Russia.**

No. 8/1/2001 (SSR)-DGAD.— Having regard to the Customs Tariff Act, 1975 as amended in 1995 and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, the Designated Authority (herein after referred to as Authority) recommended imposition of Anti Dumping Duty on imports of Hexamine (hereinafter referred to as subject goods) originating in or exported from S. Arabia and Russia (hereinafter referred to as subject countries). The preliminary findings and final findings of the Authority were published vide notifications dated 15.5.2001 and dated 15.2.2002 respectively. On the basis of findings, provisional duty and definitive anti dumping duties on the subject goods imported from subject countries were imposed by the Department of Revenue vide notifications No. 74/2001-Cus. dated 28.6.2001 and notification No. 31/2002-Cus. dated 27.3.2002 respectively.

**2. Request for Review**

WHEREAS in terms of the Customs Tariff (Amendment) Act 1995 the antidumping duty imposed shall unless revoked earlier, cease to have effect on expiry of five years from the date of such imposition.

AND WHEREAS the Rules supra require the Authority to review from time to time, the need for continued imposition of Anti Dumping Duty and if it is satisfied, on the basis of information received by it that there is no justification for continued imposition of such duty, the authority may recommend to the central government for its withdrawal. Notwithstanding the above provision the authority is required to review, on the basis of a duly substantial request made by or on behalf of the domestic industry, within a reasonable period of time prior to the date of the expiry of the

measure, whether the expiry of duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury.

AND WHEERAS, in terms of the above provisions, the Domestic Industry has approached the authority with a duly substantiated petition requesting for such a review, the Designated Authority considers that initiation of sunset review proceedings for the Anti Dumping Duty in force would be appropriate to examine the need for continued imposition of such duty to offset dumping and whether the injury would be likely to continue or recur if the duty were removed or varied or both.

### **3. Grounds for review**

The request is for continuation and enhancement of the antidumping duties in force. The request is based on the grounds that dumping has continued in spite of imposition of antidumping duty on import of the subject goods from S. Arabia and Russia and the domestic industry continues to suffer injury on account of dumping from the subject countries. The applicant has further argued that expiry of the measure against this country would be likely to result in continuation or recurrence of dumping and injury to the domestic industry.

The applicant also claims that anti-dumping duty in force is not sufficient to provide due relief to the domestic industry and revocation of anti-dumping measures would result in intensified injury to the domestic industry, therefore, the duty required to be continued for further period of five years with due enhancement.

### **4. Initiation**

Having satisfied itself on the basis of the positive evidence submitted by the domestic industry substantiating the need for a review, the Authority hereby initiates a review in accordance with Section 9 A (5) of the Act, read with Rule 23 of Antidumping Rules, to review the need for continued imposition of duties in force and whether the expiry of the duty would be likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury.

### **5. Product under Consideration**

The product involved in the present investigation is Hexa Methylene Tetramine also known as 'Hexamine' in the market. It is

a white crystalline powder with a sweet metallic taste. In the pure form, it is colourless and odourless. It crystallizes in rhombic dodecahedrons. It is also known as Ammoform, Methenamine, Crystamine, Cystogen, Urotropine. It is classified under Custom Sub-heading 2921.29 of the Customs Tariff Act, 1975. The product investigated in the original investigation was Hexamine, therefore, the same product will be covered within the scope of this investigation.

## 6. Procedure

**I)** The investigation will determine whether the expiry of the measure would be likely to lead to a continuation or recurrence of dumping and injury. The authority will examine whether the continued imposition of the duties is necessary to offset dumping and whether the injury would be likely to continue or recur if the duty were removed or varied, or both.

- i. The review will cover all aspects of Notification dated 15.2.2002
- ii. The countries involved in this review investigation are Saudi Arabia and Russia.
- iii. The period of investigation for the purpose of the present review is from 1st April 2005 to 31st March 2006.
- iv. The provisions of Rules 6,7,8,9,10,11,16,17,18,19 and 20 of the Rule supra shall be mutatis mutandis applicable in this review.

## II) Submission of Information:

The exporters in subject countries, their governments through their embassies in India, the importers and users in India known to be concerned and the domestic industry are being addressed separately to submit relevant information in the form and manner prescribed and to make their views known to the Authority in the following address:

**The Designated Authority**  
Directorate General of Anti-Dumping and Allied Duties  
Ministry of Commerce and Industry

Department of Commerce  
Udyog Bhavan  
New Delhi-110011. Fax: 91-11-23063418

Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation in the prescribed form and manner within the time limit set out below. Any party making any confidential submission before the Authority is required to make a non-confidential version of the same available to the other parties.

**III) Time Limit:**

Any information relating to the present sunset review and any request for hearing should be sent in writing so as to reach the Authority at the address mentioned above not later than forty days (40 Days) from the date of publication of this Sunset Review Notification. If no information is received within the prescribed time limit or the information received is incomplete, the Designated Authority may record its findings on the basis of the facts available on record in accordance with the Rules supra.

**IV) Inspection of Public File:**

In terms of Rule 6(7), any interested party may inspect the public file containing non-confidential version of the evidence submitted by other interested parties. In case where an interested party refuses access to, or otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

Dr. CHRISTY FERNANDEZ, Designated Authority